एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

दिसम्बर 2013
खंड XXVII अंक IV

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ

इस अंक में

6 जीसीसी देशों का आर्थिक कार्य निष्पादन
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
8 पिछली तिमाही
9 एक्ज़िम बैंक खबरों में
10 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
11 भारत के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की निर्यात संभाव्यता
12 सीएलएमवी क्षेत्र में निवेश अवसर
13 कार्यकलाप तथा साहित्य समीक्षा
14 देशों का सूक्ष्मावलोकन
15 मुद्रा की प्रवृत्तियां
16 भारत के व्यापार घाटे में 13.4% की कमी

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

लैक क्षेत्र में हालिया आर्थिक गतिविधियां

लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई (लैक) क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। विशाल बाजार, अनेक व्यापारिक खंड और संयुक्त राज्य तथा यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं से निकटता क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं।

लैक क्षेत्र का आर्थिक कार्य-निष्पादन

2009 की मंदी के बाद 2010 में लैक क्षेत्र में तीव्र सुधार हुआ तथापि क्षेत्र की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2011 में 4.6 प्रतिशत से घटकर 2012 में 2.9 प्रतिशत रह गई। यह मंदी मुख्यतः बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में थी, सामान्य वृद्धि अंशतः यूरो क्षेत्र में अनिश्चितता के कारण वैश्विक कार्यकलापों में नरमी और अंशतः गैर-तेल पण्यों की कीमतों में गिरावट के परिणाम स्वरुप थी। वृद्धि में नरमी के बावजूद, सुलभ वित्तपोषण स्थितियों की बदौलत वर्ष के दौरान अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में देशी मांग में मजबूती रही।

2012 के दौरान क्षेत्र की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों ने अंशतः, वर्ष के दौरान बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रत्युत्तर में, 2010 में शुरु हुई मौद्रिक कड़ाई प्रक्रियाओं में शिथिलता लायी। जहाँ तक राजकोषीय नीति का संबंध रहा, अधिकांश देशों ने 2012 में तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया जिससे प्राथमिक व्यय मोटे तौर पर 2011 की तरह जीडीपी के अनुरुप बढ़ा।

क्षेत्र का जीडीपी 2015 में छः ट्रिलियन यूएस डॉलर स्तर के पार हो जाने की उम्मीद है और सांकेतिक जीडीपी 2015 में 6.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है।

लैक के विदेश व्यापार की अद्यतन प्रवृत्तियां

बढ़ते भूमंडलीकरण को प्रतिबिम्बित करते हुए लैक अर्थव्यवस्थाओं के विदेश व्यापार में हाल के वर्षों में तेजी की प्रवृत्ति देखी गई है। 2002 से 2012 की अवधि के दौरान लैक क्षेत्र का कुल व्यापार (निर्यात + आयात) तिगुने से अधिक बढ़ते हुए 687.5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2258.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यह उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति लैक के निर्यात तथा आयात दोनों ही में वृद्धि से रेखांकित होती है। (चार्ट 1)

लैक क्षेत्र के देशों में, सबसे बड़े निर्यातक मेक्सिको, ब्राजील, वेनेज्युएला, अर्जेंटिना तथा चिले हैं जिनका 2012 में लैक के कुल निर्यात में 78 प्रतिशत संयुक्त हिस्सा रहा। लैक से अन्य महत्वपूर्ण निर्यातकों में कोलम्बिया, पेरु, एक्वाडोर, त्रिनिदाद एवं टुबैगो तथा पनामा शामिल हैं।

जहाँ तक आयात का संबंध है, लैक के अग्रणी आयातकों में मेक्सिको, ब्राजील, चिले, पनामा तथा अर्जेंटिना शामिल हैं जिनका 2012 में लैक के कुल आयात में 70 प्रतिशत संयुक्त हिस्सा रहा।

चार्ट 1 : लैक का विदेश व्यापार 2002-2012 (बिलियन यूएस डॉलर)

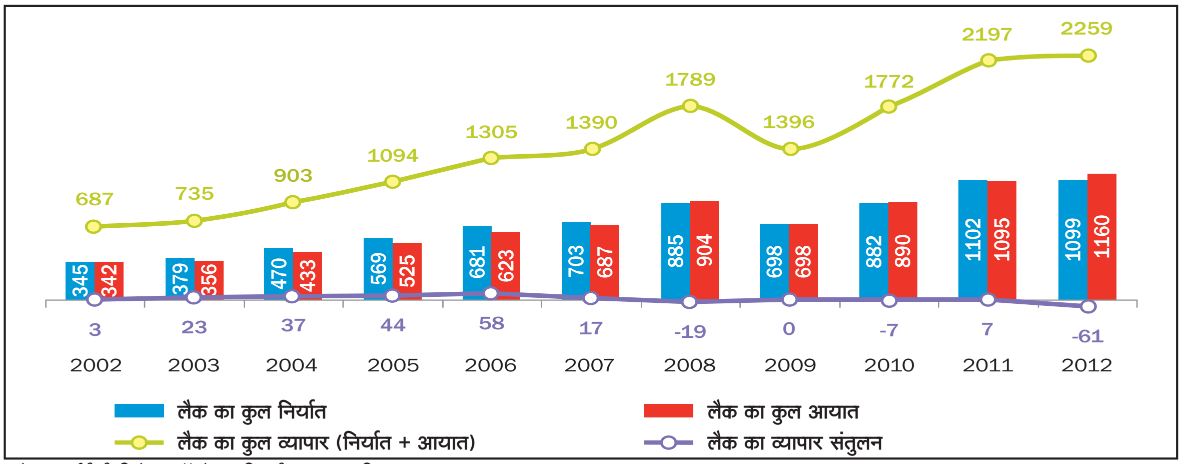

स्रोत : आईटीसी जिनेवा, कॉमट्रेड सांख्यिकीय पर आधारित।

लैक से अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हुए, खनिज ईंधन लैक से सबसे बड़ी निर्यात मद हैं जिसका 2012 में लैक के कुल निर्यात में 23.3 प्रतिशत हिस्सा रहा। लैक से निर्यात की अन्य प्रमुख मदों में शामिल हैं : परिवहन वाहन (कुल निर्यात का 8.6 प्रतिशत), इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (7.9 प्रतिशत), अयस्क, धातु-मल (स्लैग) तथा ऐश (6.9 प्रतिशत) तथा मशीनरी (6.6 प्रतिशत)।

हालांकि यूएस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, यूके और नीदरलैंड जैसे पश्चिमी विकसित देश लैक के निर्यात के लिए प्रमुख बाजार बने हुए हैं, चीन तथा भारत जैसे विकासशील देश हाल के वर्षों में प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान के रुप में उभरे हैं। 2012 में लैक के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य स्थानों में यूएस (लैक के निर्यात का 40.4 प्रतिशत), चीन (10.9 प्रतिशत), कनाडा (3.7 प्रतिशत), ब्राजील (3.4 प्रतिशत) और जापान (2.9 प्रतिशत) शामिल हैं।

लैक के निर्यात समूह, जिसमें कच्चे तेल की प्रधानता है, के विपरीत लैक का आयात समूह अपेक्षाकृत विविधीकृत है। खनिज ईंधन तथा पेट्रोलियम उत्पाद (कुल निर्यात का 14.6 प्रतिशत), मशीनरी (13.8 प्रतिशत), इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (13 प्रतिशत), परिवहन वाहन (9.1 प्रतिशत) तथा प्लास्टिक एवं उसकी वस्तुएं (4.1 प्रतिशत) 2012 में बड़ी निर्यात मदें रही।

जहाँ तक आयात स्त्रोतों का संबंध है, यूएस 36.6 प्रतिशत हिस्से के साथ लैक के आयात के लिए सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। चीन 2002 में छठे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता (लैक के कुल आयात का 2.9 प्रतिशत) से 2012 में दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता (12.3 प्रतिशत) के पायदान पर पहुँच गया है। लैक क्षेत्र को अन्य आपूर्तिकर्ताओं में ब्राजील (4.6 प्रतिशत), जर्मनी (3.9 प्रतिशत) तथा जापान (3.8 प्रतिशत) शामिल हैं।

भारत ने मर्कोसुर तथा चिले के साथ अधिमान्य व्यापार करार (PTA) पर हस्ताक्षर किये और वर्तमान में चिले के साथ अपना करार विस्तारित करने की प्रक्रिया में है।

लैक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह

लैक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह में सुधार 2011 में उल्लेखनीय रहा। तथापि, 2012 में, क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह गत वर्ष के 249.4 बिलियन यूएस डॉलर से 2.2 प्रतिशत घटकर 243.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। वर्ष के दौरान, दक्षिण अमेरिका में एफडीआई प्रवाह में महत्वपूर्ण वृध्दि मध्य अमेरिका और कैरिबिया का अंतर्वाह में गिरावट द्वारा समंजित हो गई जिससे, बदले में, क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह में समग्र गिरावट आयी।

लैक से बाह्य एफडीआई 2011 के 105.2 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2012 में 103 बिलियन यूएस डॉलर रहा जिसमें 2 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई। मेक्सिको तथा चिले ने अपने एफडीआई बहिर्वाह में जोरदार वृध्दि दर्ज की, ब्राजील से बहिर्वाह विदेशों में ब्राजीलियाई अनुषंगियों द्वारा ब्राजील में अपनी मूल कंपनी को अंतर - कंपनी ऋणों की चुकौती के उच्च स्तर से नियंत्रित रही जिससे बदले में 2012 के दौरान एफडीआई बहिर्वाह में वृध्दि समंजित हुई।

लैक के साथ भारत का व्यापार

अन्य विकासशील देशों और भारत के वैश्विक व्यापार के बढ़ते विविधीकरण के चलते लैक क्षेत्र निर्यात गंतव्य स्थान और आयात स्त्रोत दोनों ही रुपों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रुप में उभरा है। यह बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से प्रतिबिम्बित होता है जिसमें लैक के साथ भारत का कुल व्यापार (निर्यात + आयात) 2002 के 2.2 बिलियन यूएस डॉलर से लगभग 20 गुना बढ़कर 2012 में 42.5 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया हैं। **(तालिका 1)**

तालिका 1 : लैक के साथ भारत का व्यापार, 2002 -2012 (बिलियन यूएस डॉलर)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
लैक को भारत का कुल निर्यात	1.2	1.2	1.8	2.8	3.9	4.5	7.0	5.1	9.3	13.2	14.8
लैक के कुल आयात में % हिस्सा	*0.4*	*0.3*	*0.4*	*0.5*	*0.6*	*0.7*	*0.8*	*0.7*	*1.0*	*1.2*	*1.3*
लैक से भारत का कुल आयात	1.0	1.2	1.8	2.4	5.1	5.9	10.5	8.4	13.6	16.8	27.7
लैक के कुल निर्यात में % हिस्सा	*0.3*	*0.3*	*0.4*	*0.4*	*0.8*	*0.8*	*1.2*	*1.2*	*1.5*	*1.5*	*2.5*
लैक के साथ भारत का कुल व्यापार (निर्यात + आयात)	2.2	2.4	3.6	5.2	9.0	10.4	17.5	13.5	22.9	30.0	42.5
लैक के साथ भारत का व्यापार संतुलन	0.3	0.0	0.0	0.5	-1.2	-1.4	-3.4	-3.3	-4.2	-3.6	-12.9

स्त्रोत : आईटीसी जिनेवा, कॉमट्रेड सांख्यिकीय पर आधारित

कुल व्यापार में लैक को भारत के निर्यात और लैक से भारत के आयात दोनों में ही महत्वपूर्ण वृद्धि रही है किन्तु निर्यात की तुलना में आयात अधिक रहा है। लैक को भारत का कुल निर्यात 2002 के 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2012 में 14.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो इस अवधि के दौरान 12 गुनी वृद्धि दर्शाता है। लैक से भारत का कुल आयात भी इस अवधि के दौरान 1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 27.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। परिणाम स्वरुप, लैक के साथ भारत का व्यापार संतुलन, जो 2002 में 0.3 बिलियन यूएस डॉलर के अधिशेष में था, हाल के वर्षों में नकारात्मक हो गया है और 2012 में 12.9 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार घाटा रहा है।

लैक को भारत की प्रमुख निर्यात मदों में खनिज उत्पाद (2012 में कुल निर्यात का 36.6 प्रतिशत), वाहन (10.8 प्रतिशत), आर्गेनिक रसायन (6.4 प्रतिशत), औषधि उत्पाद (3.5 प्रतिशत) तथा मशीनरी (3.5 प्रतिशत) शामिल हैं।

ब्राजील लैक में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान है जिसका 2012 में लैक को भारत के कुल निर्यात में लगभग 41.6 प्रतिशत हिस्सा रहा। लैक में अन्य प्रमुख निर्यात बाजारों में बहामास (कुल निर्यात का 16.5 प्रतिशत), कोलम्बिया (6.3 प्रतिशत), चिले (4.4 प्रतिशत) और पेरू (4.3 प्रतिशत) शामिल हैं।

2001 से 2012 की अवधि के दौरान लैक में प्रमुख गंतव्य स्थानों को भारत के निर्यात की प्रवृत्तियों के

विश्लेषण से पता चलता है कि लैक को भारत के कुल निर्यात में ब्राजील, मेक्सिको, चिले, अर्जेंटिना तथा वेनेज्युएला जैसे प्रमुख गंतव्य स्थानों को निर्यात हिस्से में गिरावट आयी है, जबकि बहमास, कोलम्बिया तथा पेरू जैसे अन्य देश निर्यात में बढ़ते हिस्से के साथ महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान के रूप में उभर रहे हैं।

भारत के कच्चे तेल के आयात के लिए स्त्रोत के रूप में लैक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को प्रतिबिम्बित करते हुए, खनिज ईंधन (एचएस-27) लैक से भारत के आयात समूह में सबसे बड़ी मद है जिसका 2012 में लैक से भारत के कुल आयात में 73.4 प्रतिशत हिस्सा रहा। लैक से आयात की अन्य महत्वपूर्ण मदों में शामिल हैं : पशु, वनस्पति फैट तथा तेल, चीनी तथा कन्फेक्शनरी, लोहा एवं इस्पात, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मशीनरी।

वेनेज्युएला लैक क्षेत्र में सबसे बड़ा आयात स्त्रोत है जिसका लैक से भारत के कुल आयात में 43.8 प्रतिशत हिस्सा रहा। इसके बाद ब्राजील (लैक से कुल आयात का 19.5 प्रतिशत), मेक्सिको (12.6 प्रतिशत), चिले (9 प्रतिशत), कोलम्बिया (4.5 प्रतिशत) और अर्जेंटिना (4.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

लैक के साथ भारत के निवेश संबंध

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, लैक क्षेत्र में अनुमोदित संचयी भारतीय निवेश अप्रैल 1996-मार्च 2013 के दौरान 13.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा जिसका समग्र एफडीआई बहिवार्ह में 7.1 प्रतिशत हिस्सा रहा। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, बरमुडा, मेक्सिको तथा केमैन द्वीप भारत के एफडीआई बहिर्वाह के लिए प्रमुख गंतव्य स्थान थे **(तालिका 2)**। इसके विपरीत, अप्रैल 2000 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान लैक क्षेत्र से भारत में निवेश 2.6 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

लैक क्षेत्र में मौजूद चुनिंदा भारतीय कंपनियों* में टीसीएस (अर्जेंटिना, ब्राजील, चिले, कोलम्बिया, एक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू, उरूग्वे), ओएनजीसी विदेश लि. (अर्जेंटिना, ब्राजील, कोलम्बिया, क्यूबा, वेनेज्युएला), एचसीएल (अर्जेंटिना, बरमुडा, ब्राजील, मेक्सिको), इंफोसिस (ब्राजील, मेक्सिको), यूपीएल (अर्जेंटिना, ब्राजील, कोलम्बिया, मेक्सिको), महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (ब्राजील, केमैन द्वीप, वेनेज्युएला), हैवेल्स (अर्जेंटिना, ब्राजील, कोलम्बिया), स्ट्राइड्स अर्कोलैब (ब्राजील) तथा श्री रेणुका शुगर्स लि. (ब्राजील) आदि शामिल हैं।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अप्रैल 2000 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान लैक क्षेत्र से भारत में निवेश 2.6 बिलियन यूएस डॉलर रहा। भारत में चुनिंदा लैक कंपनियों में अन्य के साथ-साथ मार्कोपोलो, वैले, सनली फैशन, वेग, स्टेफैनिनी, जरदाऊ (ब्राजील), सिनियोपोलिस, ट्रेमेक, जेमैक, सॉफ्टटेक, प्रोलेक (मेक्सिको), इम्प्सा, गैलिलियो, टेकिंट (अर्जेंटिना), अजे ग्रुप (पेरू), तथा सीएसएवी (चिले) शामिल हैं।

*स्रोत : विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, आर विश्वनाथन, "बिजनेस विद लैटिन अमेरिका" www.businesswithlatinamerica (2 दिसंबर, 2013 को एक्सेस किया गया)

तालिका 2 : लैक क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों एवं पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में अनुमोदित भारतीय निवेश (मिलियन यूएस डॉलर)

देश	अप्रैल 1996 से मार्च 2007	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	1008.4	935.6	512.7	502.5	855.8	1582.7	1011.6	**6409.4**
केमैन द्वीप	103.9	75.9	51.9	98.18	446.3	218.9	1368.6	**2363.6**
पनामा	23.9	23.2	29.4	41.9	220.6	1889.9	19.8	**2248.6**
बरमुडा	628	0.1	219.4	104.2	-	61	340.1	**1012.6**
ब्राजील	487.1	10.1	11.8	10.98	7.1	21.1	16	**564.2**
मेक्सिको	63	7.6	10.7	10.1	13.1	4.1	6.4	**114.9**
अन्य लैक देश	73.2	68.9	49.6	19.37	91.2	49.6	77.4	**428.8**
लैक क्षेत्र में कुल	**2387.2**	**1121.4**	**885.4**	**787.2**	**1634.1**	**3827.3**	**2840**	**13482.5**
भारत का कुल ओडीआई	**31271.1**	**20947.2**	**17166.1**	**17987.3**	**43929**	**30862.9**	**26872.4**	**189036**
भारत के समग्र ओडीआई में लैक का हिस्सा	7.6	5.4	5.2	4.4	3.7	12.4	10.6	**7.1**

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक

लैक क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक

भारत के व्यापार विन्यास में लैक क्षेत्र का महत्व भारत सरकार की कई पहलों से आंका जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है -"फोकस : लैक" कार्यक्रम जिससे भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) घनिष्ठ रुप से जुड़ा हुआ है। लैक क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंक एक भागीदार संस्था के रुप में कार्य कर रहा है। क्षेत्र के साथ संबंध बनाने के प्रति प्रतिबद्धता की झलक एक्ज़िम बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यकलापों में दिखाई देती है। एक्ज़िम बैंक मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में परियोजनाओं के निष्पादन में भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देने और वित्तपोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस दिशा में एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय औद्योगिक टर्न-की परियोजनाओं, सिविल निर्माण संविदाओं, आपूर्तियों और तकनीकी एवं परामर्शी सेवा संविदाओं के लिए निधिक तथा गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान करता है। एक्ज़िम बैंक आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से विकासात्मक तथा संरचनात्मक परियोजनाओं, उपकरणों, माल तथा सेवाओं का आयात करने में इन देशों के क्रेताओं को समर्थ बनाने के लिए ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करता है। इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से अपने परिचालनों को वैश्वीकृत करने वाली भारतीय कंपनियों के प्रयासों में सहायता करता है। लैक क्षेत्र में संस्थागत संबंध निर्मित करने की दिशा में एक्ज़िम बैंक ने क्षेत्र में कई संस्थाओं के साथ सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किये हैं तथा क्षेत्र में भारत की व्यापार तथा निवेश संभावनाओं से संबंधित मुद्दों पर आवधिक रुप से शोध अध्ययन भी प्रकाशित किये हैं।

दोनों ही क्षेत्रों के सरकारी प्रतिनिधियों तथा उद्यमियों को एक साथ लाने के प्रयास में, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एक्ज़िम बैंक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सहभागिता में नई दिल्ली में 9-10 दिसम्बर, 2013 के दौरान "पांचवां भारत-लैटिन अमेरिकी तथा कैरिबियाई सम्मेलनः कारोबारी भागीदारिता बढ़ाना" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

यथा दिसम्बर 2013 को नई परियोजनाएं

देश/निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
ग्रामीण ऊर्जा एजेंसी प्रापण प्रबंध इकाई 2 री मंजिल, कमरा नं. 214 मवासिलियानो टॉवर्स, 20 सैम नुजोमा रोड 14414 दार एस सलाम, तंजानिया **संपर्क :** टेली. : +0 22 2412001-3 फैक्स : +0 22 2412007 ई-मेल : info@rea.go.tz	**ऊर्जा विकास एवं अभिगम विस्तार परियोजना** परियोजना के कार्यक्षेत्र में किलोम्बेरो जिला, मोरोगोरो क्षेत्र के लिए कम लागत पर विद्युतीकरण के लिए 33 केवी तथा एलवी वितरण लाइन का निर्माण कार्य शामिल है।	**विश्व बैंक** 105 मिलियन यूएस डॉलर
ग्रामीण पुनर्वास तथा विकास मंत्रालय ताशकिलत रोड, दारुल-अमन काबुल, अफगानिस्तान **संपर्क :** परियोजना निदेशक ई-मेल : m.hanifi@nspafghnistan.org n.azimi@nspafghanistan.org	**एनएसपी-III परियोजना** परियोजना में अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य सरकार के ग्रामीण पुनर्वास तथा विकास मंत्रालय के लिए तीस हार्ड-टॉप स्टेशन वैगनों की खरीद शामिल है।	**विश्व बैंक** 40 मिलियन यूएस डॉलर
विकास एवं निवेश विभाग एडी इलेक्ट्रानी ना मेकदोनिजा स्ट्रीट 11, आक्टोमवरी 9, स्कोपजे मैसीडोनिया गणराज्य **संपर्क :** श्री ईवान ट्रपेस्की टेली. : +389 23149-101 फैक्स : +389 23224-492 ई-मेल : ivan.trpeski@elem.com.mk	**बास्कोव मोस्ट हाइड्रो-पॉवर परियोजना** परियोजना में रॉकफिल बाँध, विपथन प्रणाली, विद्युत जलमार्ग, पावरहाउस का निर्माण कार्य तथा संस्थापना और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सहित संबंधित सिविल कार्य शामिल है।	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** 84 मिलियन यूरो
वित्त मंत्रालय, किरगिज गणराज्य 58 इर्किनदिक बाउलेवार्ड 720040 बिष्केक किरगिज गणराज्य **संपर्क :** सुश्री गुलमीरा सम्सालीवा मुख्य विशेषज्ञ टेली. : +996-312-660506	**ओश ऑटो ट्रान्सपोर्ट एंटरप्राइज का कॉरपोरेट विकास** परामर्शदाता के विशिष्ट कार्यों में शामिल होंगे :- i. वित्तीय तथा परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार संबंधी कार्यक्रम तैयार करना ii. फ्लीट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर रखरखाव तथा मरम्मत कार्यक्रम विकसित करना, और iii. कार्य-कुशलता, राजस्व तथा लागत कवरेज बढ़ाने और उपभोक्ताओं की माँग तथा प्राथमिकताओं को पूरा करने संबंधी उपायों से युक्त एक दीर्घकालिक कारोबार योजना तैयार करना।	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** 0.25 मिलियन यूरो
सिलोन विद्युत बोर्ड 7 वीं मंजिल, 50, सर चित्तमपालम ए. गार्डिनर मवाथा कोलम्बो 2 श्री लंका **संपर्क :** उमप्र (आरई परियोजना एवं प्रापण) टेली. : +94 11-2055942 फैक्स : +94 11-2055944 ई-मेल : udompage@yahoo.com	**संधारणीय बिजली क्षेत्र सहायता परियोजना** परियोजना में अनियाकांडा, अम्बालनगोडा तथा काटुनायक ग्रिड उप-स्टेशनों में 40 मेगावॉट एआर ब्रेकर स्विच कैपासिटर बैंकों की संस्थापना के लिए माल तथा संबंधित सेवाओं का प्रापण, आपरेटिंग तथा माउंटिंग स्ट्रक्चर वाली बीएससी बैंक स्विचिंग के लिए 15 थ्री फेज सर्किट ब्रेकर की खरीद भी शामिल है।	**एशियाई विकास बैंक** 120 मिलियन यूएस डॉलर

देश/निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
सड़क विभाग भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा परिवहन मंत्रालय बिशालनगर काठमांडु, नेपाल **संपर्क :** परियोजना निदेशक (एडीबी) टेली. : +977-1 4437492 फैक्स : +977-1 4437488 ई-मेल : pdadb@wlink.com.np	**सैसेक सड़क संयोजकता परियोजना** कार्य में अन्य के साथ-साथ सड़क-मार्ग खोदाई तथा तटबन्धन, मोटर-चालनीय आरसीसी टी-ग्रिडर, प्री-स्ट्रेस्ड तथा ठोस स्लैब पुलों का निर्माण; सड़क खंड का पुनर्निर्धारण और बगली नालियों, भराव संरचनाओं का निर्माण शामिल है।	**एशियाई विकास बैंक** 24.9 मिलियन यूएस डॉलर
जियोथर्मल डेवलपमेंट कंपनी लि. रिवरसाइड ड्राइव पो. बॉ. 100746-00101 नैरोबी केन्या **संपर्क :** प्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) ई-मेल : asaat@gdc.co.ke	**मेनेनगई चरण I जियोथर्मल परियोजना** परियोजना में 5 से 10 मेगावॉट मॉड्युलर पॉवर प्लांट की आपूर्ति तथा स्थापना और जीडीसी प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शामिल है। परियोजना का स्थान मेनेनगई जियोथर्मल फील्ड, नाकुरु काउंटी, केन्या है।	**अफ्रीकी विकास बैंक** 165 मिलियन यूएस डॉलर
ईथियोपिया सड़क प्राधिकरण रास अबेबे आरगे स्ट्रीट 4 थी मंजिल, कमरा नं. 408 अदिस अबाबा ईथियोपिया **संपर्क :** महा निदेशक का कार्यालय टेली. : +251 11 515 66 03 फैक्स : +251 11 551 48 66	**माडजो-हवासा राजमार्ग परियोजना - चरण I** संविदा में माडजो तथा मेकी नगरों के बीच 56 किमी नई 4 पथ दोहरे वाहनमार्ग की विस्तृत इंजीनियरिंग, डिज़ाइन तथा निर्माण शामिल होगा। कार्य में अलेम टेना तथा मेकी के बीच छोटे कस्बों को सड़क से जोड़ना शामिल होगा।	**अफ्रीकी विकास बैंक** 220 मिलियन यूएस डॉलर

भारतीय कंपनियों/परामर्शदाताओं को प्राप्त चुनिंदा संविदाएं

केईसी इंटरनेशनल लि., मुंबई	**यूरोपीय निवेश बैंक** से निधिक सहायता प्राप्त - तंजानिया में 400 केवी ओवरहेड ट्रान्समिशन लाइन (लॉट 3 : सिंगिदा-शिन्यांगा-228 किमी) के लिए संविदा। **यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** से निधिक सहायता प्राप्त - क़ज़ाखस्तान में ओसाकारोवका पारेषण परियोजना की मौजूदा 220 केवी डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन के पुनरुत्थान हेतु संविदा।
ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कन्सल्टेंट्स लि., मुंबई	**विश्व बैंक समूह** से निधिक सहायता प्राप्त - किरगिज गणराज्य की स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा परियोजना के लिए वर्ष 2012-2014 के लिए प्रापण पश्चात समीक्षा (लेखा-परीक्षा)।
कॉस्मोस इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली एवं मालैब साइंटिफिक ईक्विपमेंट लि., हैदराबाद	**विश्व बैंक समूह** से निधिक सहायता प्राप्त - ईथियोपिया के कृषि विकास कार्यक्रम के लिए मिट्टी प्रयोगशाला उपकरणों, कांच, प्लास्टिक तथा सिरैमिक पात्र, अतिरिक्त पुरजों, रसायनों तथा अभिकर्मकों की आपूर्ति हेतु संविदा।
त्रिवेणी टरबाइन लि., नोएडा	**विश्व बैंक समूह** से निधिक सहायता प्राप्त - औद्योगिक उद्यम परियोजना के लिए उजबेकिस्तान की ऊर्जा दक्षता सुविधा के लिए 6 मेगावॉट के टरबाइन पॉवर के साथ बाष्प टरबाइन संयंत्र के प्रापण, संस्थापना, पर्यवेक्षण, चालू करना तथा समायोजन कार्य और प्रशिक्षण के लिए संविदा।
वैपकॉस लि., नई दिल्ली	**विश्व बैंक समूह** से निधिक सहायता प्राप्त - रवांदा के पश्चिमी प्रांत जिले न्यामाशेके में सिंचाई बाँध के साथ कमीरानजोवु दलदल भूमि (140 हेक्टेयर) के विकास हेतु तकनीकी डिज़ाइन अध्ययन के लिए संविदा।
डेवलपमेंट इन्वाइरनर्जी सर्विसेज़ लि. (डीईएसएल), नई दिल्ली	**विश्व बैंक समूह** से निधिक सहायता प्राप्त - स्वच्छ वायु परियोजना के अंतर्गत उलानबातर जिला ऊष्मा आपूर्ति सुधार हेतु संभाव्यता अध्ययन की तैयारी के लिए संविदा।

जीसीसी देशों का आर्थिक कार्य निष्पादन

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) छः अरब देशों नामतः संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) , सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत तथा बहरीन का एक राजनीतिक तथा आर्थिक संघ है । हाल के वर्षों में, जीसीसी देशों ने मुख्यतः ऊँची हाइड्रोकार्बन कीमतों तथा उत्पादन की बदौलत जोरदार आर्थिक वृध्दि दर्ज की है । बढ़ी हुई निर्यात आय से चालू खाता अधिशेष पर्याप्त हो गया है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृध्दि हुई है । साथ ही, तेल की ऊँची कीमतों ने सरकारी व्यय तथा निवेश में वृध्दि को सुगम बनाया है जिससे गैर-हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में भी कार्यकलापों में तेजी आयी है । अधिकांश जीसीसी देश तेल पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक कार्य-निष्पादन तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ घटता-बढ़ता रहता है ।

जीसीसी देशों का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं को (तेल एवं हाइड्रोकार्बन उन्मुख होने से) सेवा क्षेत्र की ओर विशाखित करना है । इस दिशा में, जीसीसी देशों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कानून में संशोधन कर, सार्वजनिक-निजी भागीदारी शुरू कर और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित कर आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किये हैं । जीसीसी अर्थव्यवस्थाओं में, बहरीन तथा ओमान 2011 के दौरान अरब स्प्रिंग विद्रोह से प्रभावित हुए । राजनीतिक तथा सामाजिक अशांति की मार बहरीन की सेवा उन्मुख अर्थव्यवस्था पर पड़ी जिससे निवेशक विश्वास कमजोर हुआ और फलस्वरूप जीडीपी वृध्दि दर 1.9 प्रतिशत रही जो 2004 से अब तक सबसे कम है । तथापि, 2011 में राजकोषीय प्रोत्साहन और जीसीसी भागीदारों से सहायता पैकेज से 2012 में वृध्दि को 3.4 प्रतिशत तक ले जाने में सहायता मिली है । ओमान में, विद्रोह के फैलाव का प्रभाव 2011 में कारोबार पर पड़ा । हाइड्रोकार्बन क्षेत्र ओमान में वृध्दि का मुख्य संवाहक रहा है जिससे जीडीपी वृध्दि दर 2011 के 4.3 प्रतिशत की तुलना में 2012 में 7.1 प्रतिशत रही । कुवैत में भी वृध्दि का प्राथमिक संवाहक तेल रहा है । 2011 में तेल उत्पादन में वृध्दि के कारण वास्तविक जीडीपी में उस वर्ष के दौरान 6.3 प्रतिशत की वृध्दि हुई । तथापि, घरेलू राजनीतिक तनावों के चलते वृध्दि दर 2012 में 4.8 प्रतिशत हो गई। कतर में, गैस विस्तार परियोजनाओं की पूर्णता ने वृध्दि दर पर विराम लगा दिया, जिससे वृध्दि दर 2011 में 13 प्रतिशत की तुलना में 2012 में 6.2 प्रतिशत रही ।

सऊदी अरब में वास्तविक जीडीपी वृध्दि दर ने अपनी गति पकड़ी और 2009 में 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2010 में 7.4 प्रतिशत और फिर 2011 में 8.5 प्रतिशत हो गई । इसकी मुख्य वजह सरकारी प्रोत्साहन और लीबिया में आपूर्ति व्यवधान को पूरा करने के लिए सऊदी तेल उत्पादन में वृध्दि रही है । तथापि वृध्दि दर 2012 में घटकर 6.8 प्रतिशत रह गई । यूएई के मामले में, अर्थव्यवस्था दुबई संकट के परिणामों से धीरे-धीरे उबर रही है । निजी खपत, निर्यात तथा कच्चे तेल के बढ़े हुए उत्पादन के चलते वृध्दि 2012 में 4.4 प्रतिशत तक आ गई ।

जीसीसी क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (भारतीय एक्ज़िम बैंक) भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इस दिशा में भारतीय एक्ज़िम बैंक भारतीय परियोजना निर्यातकों को समुद्रपारीप औद्योगिक टर्न-की परियोजनाओं, सिविल निर्माण संविदाओं, आपूर्तियों और तकनीकी एवं परामर्शी सेवा संविदाओं के लिए निधिक तथा गैर-निधिक दोनों ही सुविधाएं प्रदान करता है । जीसीसी देश भारत के परियोजना निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य स्थान हैं । मार्च 2013 को जीसीसी क्षेत्र में भारतीय परियोजना निर्यातकों को प्राप्त परियोजना संविदाओं का मूल्य ₹ 37,814 करोड़ रहा, जो भारतीय एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कुल परियोजना निर्यात (₹ 1,16,019 करोड़) का 32.6 प्रतिशत रहा ।

एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा अपने परिचालनों को वैश्वीकृत करने के प्रयासों में सहायता देने के उद्देश्य से भारतीय कंपनियों के संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से समुद्रपारीय निवेश में सहायता देने का एक कार्यक्रम भी चलाता है । भारतीय एक्ज़िम बैंक ने इंजीनियरिंग, धातु तथा धातु प्रसंस्करण, प्लास्टिक तथा पैकेजिंग, कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप जैसे क्षेत्रों में ओमान, सऊदी अरब और यूएई में कई संयुक्त उद्यमों को सहायता प्रदान की है ।

भारतीय एक्ज़िम बैंक भारत तथा जीसीसी क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए गठजोड़ों तथा संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है । इस दिशा में, भारतीय एक्ज़िम बैंक ने आर्थिक विकास बोर्ड, बहरीन, कतर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, कतर; तथा शारजाह वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, यूएई के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं । इसके अलावा, भारतीय एक्ज़िम बैंक ने जीसीसी देशों के लिए एक निर्यात ऋण एवं गारंटी सुविधा की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन भी शुरू किया है ।

दुबई में भारतीय एक्ज़िम बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय है जो क्षेत्र में नई परियोजनाओं की पहचान करता है और भारतीय परियोजना निर्यातकों को बैंकों से गारंटी सुविधा प्राप्त करने में सहायता देने के अलावा कारोबार अवसरों के बारे में जानकारी (लीड्स) भी प्रदान करता है ।

व्यापार तथा निवेश अवसरों की पहचान करने के उद्देश्य से, एक्ज़िम बैंक ने 'खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंध : आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना' विषय पर एक शोध अध्ययन भी प्रकाशित किया है ।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष बल दिया है । एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सॉवरिन सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण व्यवस्थाएं प्रदान करता है जो बदले में अपने देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थागित ऋण शर्तों पर विकासपरक और बुनियादी परियोजनाएं, उपकरण, माल एवं सेवाएं आयात करने के लिए ऋण-सुविधाएं प्रदान करती हैं । भारतीय निर्यातक बिना दायित्व के शिपिंग दस्तावेज़ों के परक्रामण पर एक्ज़िम बैंक से पात्र राशि का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं । एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है । सरकार के आदेश पर प्रदान की जाने वाली ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को माल की शिपिंग पर संविदा मूल्य की 100 प्रतिशत राशि की अपफ्रंट प्रतिपूर्ति करता है । बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत माल एवं सेवाएं भारत से मँगायी जाएं । एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों को जोखिम रहित, दायित्व-रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं ।

एक्ज़िम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया और जीआईएस के 75 देशों को शामिल करते हुए वर्तमान में 9.71 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण-वचनबध्दताओं के साथ 180 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं जो भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं । इन ऋण-व्यवस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन, संचार, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा पारेषण, ग्रामीण विद्युतीकरण में परियोजनाओं के निर्यात को उत्प्रेरित किया है। भारतीय परियोजना निर्यात के लिए प्रदान की जा रही ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देश में विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय विशेषज्ञता और परियोजना निष्पादन क्षमताओं का भी प्रदर्शन करती हैं ।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश एवं सहयोग से अक्तूबर-दिसम्बर 2013 तिमाही के दौरान निम्नलिखित दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं :

- रवांडा सरकार को (i) निर्यात लक्ष्यित आधुनिक सिंचित कृषि परियोजना, तथा (ii) रवांडा में निर्यात लक्ष्यित आधुनिक सिंचित कृषि परियोजना के विस्तार के वित्तपोषण के लिए 120.05 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था । यह भारत सरकार के आदेश पर रवांडा को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई तीसरी ऋण-व्यवस्था है । 20 मिलियन यूएस डॉलर तथा 60 मिलियन यूएस डॉलर की पहली दो ऋण-व्यवस्थाएं रवांडा में न्याबोरोंगो हाइड्रो पॉवर परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थीं ।

- सिनेगल में आधुनिक बूचड़खाना, मांस प्रसंस्करण, शीत भंडारण, चर्मशोधन शाला तथा बाजार की स्थापना के वित्तपोषण के लिए सिनेगल सरकार को 41.60 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था। एक्ज़िम बैंक ने सिनेगल सरकार को इसके पहले कुल 149.45 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 9 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं । ये ऋण-व्यवस्थाएं विभिन्न प्रयोजनों जैसे सिंचाई परियोजना, आईटी प्रशिक्षण परियोजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना, मत्स्य पालन विकास परियोजना, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, वाहनों की आपूर्ति तथा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदान की गई थीं ।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया संपर्क करें

सुश्री गीता पूजारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड,
मुंबई - 400 005.

फोन : (022) 22172310
फैक्स : (022) 22182460
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

परियोजना निर्यात : एक्ज़िम बैंक की भूमिका

परियोजना निर्यात किसी भी देश के आर्थिक विकास का मापदंड होते हैं। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) परियोजना निर्यात के संवर्धन के लिए समन्वयकर्ता तथा सुलभकर्ता की भूमिका निभाता है। बैंक विदेशी औद्योगिक टर्न-की परियोजनाओं, सिविल निर्माण संविदाओं, आपूर्तियों तथा तकनीकी एवं परामर्शी सेवा संविदाओं को सम्मिलित करते हुए परियोजना निर्यात पर कार्य दल के केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करता है ।

एक्ज़िम बैंक भारतीय परियोजना निर्यातकों को निधिक सहायता, गारंटी सुविधाएं और समुद्रपारीय परियोजनाओं के लिए अन्य देश से आयात के प्रति उनकी ओर से साखपत्र जारी करने सहित व्यापक वित्तपोषण पैकेज प्रदान करता है। भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बीसी-एनईआईए) प्रोग्राम के अंतर्गत क्रेता ऋण की शुरूआत भी की है । बीसी-एनईआईए एक अनोखी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को एक सुरक्षित व दायित्व-रहित वित्तपोषण विकल्प प्रदान करती है तथा विकासशील देशों में मध्यावधि या दीर्घावधि आधार पर आस्थगित ऋण के जरिए पुराने तथा नए बाजारों में प्रभावी बाजार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करती है ।

अभी तक एक्ज़िम बैंक द्वारा ₹133,088 करोड़ (लगभग 21.3 बिलियन यूएस डॉलर) मूल्य की परियोजना निर्यात संविदाएं 92 भारतीय कंपनियों द्वारा एशिया, अफ्रीका तथा सीआईएस के 73 देशों में निष्पादन के अधीन थीं ।

दूसरी तिमाही में निर्यात में वृध्दि के चलते चालू खाते के घाटे (कैड) में गिरावट

भारत का चालू खाता घाटा (कैड) वर्ष 2013-14 की जुलाई-सितम्बर तिमाही (दूसरी तिमाही) में तेजी से घटकर 5.2 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) हो गया, जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में यह 21 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 5 प्रतिशत) था। अप्रैल-जून तिमाही (पहली तिमाही) के दौरान कैड जीडीपी का 4.9 प्रतिशत था। इस गिरावट की मुख्य वज़ह निर्यात में वृध्दि और स्वर्ण आयात में गिरावट थी। तिमाही के दौरान पण्य निर्यात विशेषकर 'वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों', 'चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों' और 'रसायनों' के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की बदौलत 11.9 प्रतिशत बढ़कर 81.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। जहाँ तक आयात का संबंध है, स्वर्ण आयात 2012-13 की दूसरी तिमाही में 11.1 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में घटकर 3.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

सितम्बर 2013 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 400.3 बिलियन यूएस डॉलर

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने यथा सितम्बर 2013 के अंत में भारत के विदेशी ऋण के आंकड़े जारी किये। भारत का कुल विदेशी कर्ज 400.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो मार्च 2013 के अंत में विदेशी ऋण के स्तर से 9 मिलियन यूएस डॉलर कम है। कुल विदेशी ऋण में से दीर्घावधि ऋण 305.5 बिलियन यूएस डॉलर (कुल ऋण का 76.3 प्रतिशत) रहा जो मार्च 2013 के स्तर से 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि अल्पावधि ऋण 2 प्रतिशत घटकर 94.8 बिलियन यूएस डॉलर (कुल विदेशी ऋण का 23.7 प्रतिशत) रहा। सरकारी (सॉवरिन) विदेशी ऋण मार्च 2013 के अंत में 81.7 बिलियन यूएस डॉलर (20.4 प्रतिशत) की तुलना में सितम्बर 2013 के अंत में 77.3 बिलियन यूएस डॉलर (कुल विदेशी ऋण का 19.3 प्रतिशत) रहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा एफएसएलआरसी पर पहली कार्रवाई

भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। एफएसएलआरसी ने सिफारिश की है कि डीआईसीजीसी को रेज़ूलेशन कॉरपोरेशन में सम्मिलित किया जाए। एफएसएलआरसी की रिपोर्ट में बाजार के मॉनीटरिंग कार्यों, कमोडिटी, बीमा तथा पेंशन विनियामकों का विलय करके मौजूदा वित्तीय प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाया जाए। डीआईसीजीसी की प्राधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करने के अलावा, वित्त मंत्रालय ने सरकार को अध्यक्ष सहित निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार देने का भी सुझाव दिया है। वर्तमान में, अध्यक्ष तथा बोर्ड की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। सभी प्रस्तावित परिवर्तन डीआईसीजीसी संशोधन बिल, 2013 में पारित अनुसार हैं।

इंफ्रा क्षेत्र को बढ़ते बैंक ऋण पर आरबीआई की चेतावनी

आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ते बैंक ऋणों पर चिन्ता जताई है तथा बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव शुरू होने से पहले ही इसका समाधान करने की जरूरत पर जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में दबाव बढ़ रहा है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक ऋण जो 1999-2000 में 7243 करोड़ रुपये था, 2012-13 में 100 गुना से अधिक बढ़कर 786,045 करोड़ रुपये हो गया है। इस गंभीर दबाव के चलते बैंकों का, सकल एनपीए मार्च 2014 के अंत तक 4.4 प्रतिशत तक (जून 2013 में 3.9 प्रतिशत से) बढ़ सकता है। आरबीआई ने यह भी सचेत किया है कि इसके चलते बैंकों को बासेल III में अंतरण में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बासेल III के अनुसार बैंकों को 8 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखना है। आरबीआई ने भारतीय बैंकों के लिए न्यूनतम 9 प्रतिशत सीएआर निर्धारित किया है।

आरबीआई द्वारा निर्यात-आयात लेनदेनों के लिए अन्य पक्ष भुगतान की अनुमति

आरबीआई ने निर्यात-आयात लेनदेनों के लिए कुछ शर्तों के साथ अन्य पक्ष द्वारा भुगतान की अनुमति प्रदान की है। मुख्य शर्तों में आरबीआई ने कहा कि निर्यात लेनदेनों के लिए अविकल्पी आदेश त्रिपक्षीय करार द्वारा समर्थित होना चाहिए, जबकि आयात लेनदेनों के लिए अविकल्पी क्रय आदेश / त्रिपक्षीय करार होना चाहिए। आरबीआई ने यह भी कहा है कि निर्यात तथा आयात लेनदेनों के लिए अन्य पक्ष भुगतान वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) अनुपालक देश से और सिर्फ बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आना चाहिए। प्रतिबंधित कवर देशों के ग्रुप II के देशों (जैसे सूडान, सोमालिया आदि) को निर्यात के मामले में, भुगतान खुले कवर वाले देश से प्राप्त किये जा सकते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अन्य पक्ष भुगतान के लिए आयात लेनदेन की राशि 100,000 यूएस डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे आवश्यक समझे जाने पर संशोधित किया जा सकता है।

आरबीआई द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों में सुधार का अनुमोदन

आरबीआई ने त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना में दूरगामी सुधार लाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पर गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। प्राथमिक सहकारी समितियों की आस्तियां तथा देयताएं अब केन्द्रीय / राज्य सहकारी बैंकों को अंतरित हो जाएंगी। जिन राज्यों में केन्द्रीय या राज्य सहकारी बैंक कोर बैंकिंग प्रणालियों में पूरी तरह से कॉम्प्यूटरीकृत हैं वहां प्राथमिक सहकारी समितियाँ उनके कारोबारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से जारी परिपत्र राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सुधार का खाका प्रस्तुत करता है। प्राथमिक सहकारी समितियाँ न तो अब स्वयं जमाराशियाँ स्वीकार करेंगी और न ही किसी प्रकार का ऋण देंगी।

एक्ज़िम बैंक के सीएमडी श्री टी. सी. ए. रंगनाथन सेवानिवृत्त; श्री अनुराग जैन ने सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया

भारतीय निर्यात-आयात बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री टी. सी. ए. रंगनाथन 30 नवम्बर 2013 को अधिवार्षिता आयु प्राप्त करने पर अपने पद से सेवानिवृत्त हो गये। श्री रंगनाथन अप्रैल 2010 से बैंक के मुख्य कार्यपालक का कार्यदायित्व संभाल रहे थे। श्री रंगनाथन के नेतृत्व में एक्ज़िम बैंक ने देश की प्रमुख निर्यात वित्त संस्था के रूप में कारोबार संवर्धन और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। श्री अनुराग जैन (आईएएस : 1989), संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेश एवं सीवीओ), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को तब तक के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है जब तक कि भारत सरकार द्वारा नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर दी जाती। श्री अनुराग जैन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्होंने मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिरैक्यूज, यूएसए से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। श्री अनुराग जैन पंजाब नेशनल बैंक, नैशनल इंश्योरेंस कं लि. तथा आईएफसीआई लि. के बोर्ड में हैं।

एक्ज़िम बैंक का अध्ययन लचीले श्रम बाजार विनियमों की सिफारिश करता है

'चुनिंदा देशों के श्रम कानूनों की तुलना' : शीर्षक से प्रकाशित एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि भारत को अपनी श्रम नीतियों को अपने प्रतिस्पर्धियों की नीतियों के अनुरूप बनाना चाहिए ताकि भारत कारोबार सहयोग करारों (जैसे एफटीए/पीटीए, सीईसीए) का प्रभावी रूप से फायदा उठा सके और औद्योगिकीकरण, निर्यात विकास तथा देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश आकृष्ट किया जा सके। अध्ययन के अनुसार, भारत के निर्यात में गिरावट तथा आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा बढ़ा है। इससे उपजे उच्च चालू खाता घाटे (कैड) अध्ययन पर चिंता व्यक्त की गई है तथा बताया गया है कि आयात में वृद्धि का एक प्रमुख कारण भारतीय विनिर्माण के कुछ क्षेत्रों में क्षमताओं के निम्न स्तर का होना है। भारत के श्रम कानूनों की 20 देशों के साथ 15 मानदंडों पर तुलना करते हुए अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि (क) सामूहिक सौदेबाजी के लिए ट्रेड यूनियनों का गठन और मान्यता, (ख) स्थायी कार्यों के लिए ठेका श्रमिकों को रखने की प्रक्रिया और (ग) औद्योगिक विवादों के निपटान की प्रक्रिया तीन प्रमुख मानदंडों पर भारत के समकक्षी अधिकांश देशों ने बदलती स्थितियों के अनुरूप कानूनों को संशोधित किया है। भारत को भी अपनी जरूरतों के अनुरूप और समकक्षी देशों से सबक लेते हुए अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए। ऐसा करते समय, मजदूरों के हितों का ध्यान रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त प्रतिकर आदि सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी किये जाने चाहिए। इससे विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

एक्ज़िम बैंक ने हस्तशिल्प कारीगरों की सहायता के लिए एनसीडीपीडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये

एक्ज़िम बैंक और राष्ट्रीय डिज़ाइन तथा उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी) ने भारतीय हस्तशिल्प निर्माताओं और शिल्पकारों की सहायता करने के लिए एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। सहमति ज्ञापन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की बदलती अभिरुचियों को पूरा करने के लिए कंपनियों / शिल्पकारों के लिए संयुक्त रूप से कार्यशालाओं के आयोजन, डिज़ाइन, उत्पाद तथा कौशल विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और निर्यात क्षमता के सृजन में सहायता प्रदान करने के संबंध में दोनों संस्थाएं मिल-जुलकर कार्य करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती पनबाका लक्ष्मी, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यपालक निदेशक श्री राकेश कुमार और ईपीसीएच के अध्यक्ष श्री लेखराज माहेश्वरी की उपस्थिति में इस एमओयू पर एक्ज़िम बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री डेविड रस्कीना और एनसीडीपीडी के अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) श्री एस एस गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

एक्ज़िम बैंक ने एसीएएसएच और एनएचडीसी के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किये

एक्ज़िम बैंक ने हथकरघा प्राथमिक सोसाइटियों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली एक पंजीकृत सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेशन्स एंड एपेक्स सोसाइटीज ऑफ हैंडलूम (एसीएएसएच)- और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)- हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के साथ एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किये हैं। एमओसी के अंतर्गत, तीनों संस्थाएं उत्पाद एवं पैकेजिंग सुधार, चैनल भागीदार विकसित करने, बाजार सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा भारत से हथकरघा / हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आपस में सूचना के आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगी। भारत की प्रमुख निर्यात वित्त संस्था के रूप में एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक्ज़िम बैंक घरेलू तथा विदेशी बाजारों में अवसरों की पहचान करने सहित निर्यातक फर्मों के उत्पादों एवं सेवाओं के लिए वितरकों / क्रेताओं / भागीदारों का पता लगाने में भी सहायता करता है। बैंक भारतीय हस्तशिल्प कंपनियों के भूमंडलीकरण प्रयासों में सहायता करता है। अपने ग्रासरूट पहल तथा विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक निर्यात उन्मुख तथा ग्रामीण फोकस रखने वाली भारतीय कंपनियों तथा अलाभकारी संगठनों की भी मदद करता है।

भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। भारत के कुल खाद्य बाजार में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का 32 प्रतिशत हिस्सा है। इस उद्योग के 2013 में 121 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का होने का अनुमान है। 2015 तक उद्योग के 175.2 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के स्तर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। यह भारत में एक सबसे बड़ा उद्योग है और उत्पादन, उपभोग तथा निर्यात की दृष्टि से अन्य भारतीय उद्योगों में पांचवे स्थान पर आता है। देश के जीडीपी में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का लगभग 12.7 प्रतिशत योगदान है और यह क्षेत्र देश में लगभग 60 प्रतिशत रोजगार के अवसर प्रदान करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान यह उद्योग भारत की जीडीपी वृद्धि दर की लगभग दुगुनी दर से बढ़ा है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार, 2011-12 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का प्रदर्शन विनिर्माण क्षेत्र से बेहतर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 3 प्रतिशत के आस-पास ही रही है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस क्षेत्र में कुल 35,838 पंजीकृत इकाइयाँ हैं जिनमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और मूल्य की दृष्टि से इनका उत्पादन लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये मूल्य का है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में फैक्टरियों का राज्य-वार वितरण

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2010-11 के अनुसार, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फैक्टरियों की कुल संख्या 35,838 है। इस उद्योग में सबसे अधिक फैक्टरियाँ आंध्र प्रदेश में हैं जिनका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उद्योग में कुल फैक्टरियों में लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद तमिलनाडु (15 प्रतिशत) और पंजाब (8.3 प्रतिशत) का हिस्सा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश की गई पूंजी

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने निवेशित पूंजी की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। एएसआई 2010-11 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश की गई पूंजी 2010-11 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान 22.17 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर (एएजीआर) से बढ़ते हुए 2.5 लाख करोड़ रुपये रही। **(तालिका)**

निर्यात

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यतः निर्यातोन्मुख है। प्रसंस्कृत खाद्यों का निर्यात हाल के वर्षों में बढ़ा है **(चार्ट)**। प्रसंस्कृत खाद्य के लिए भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान यूएसए, यूरोप, मध्य पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशिया हैं। भारत के प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में मुख्यतः आम गूदा, सूखी तथा परिरक्षित सब्जियाँ, अचार एवं चटनी, भैंस का मांस, बासमती चावल तथा झींगे शामिल हैं। आम का गूदा सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, नीदरलैंड तथा हाँगकाँग को निर्यात किया जाता है। अचार तथा चटनी के मामले में लोकप्रिय बाजार यूएसए, यूके, यूएई, जर्मनी तथा सऊदी अरब हैं। टमाटर पेस्ट, मुरब्बा तथा जेली जैसी अन्य मदें यूएसए, रूस, यूके, यूएई तथा नीदरलैंड को निर्यात की जाती हैं। सब्जियों का निर्यात मुख्यतः मीडिल ईस्ट, यूरोप, यूके तथा सिंगापुर को किया जाता है।

चार्ट : भारत से प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात

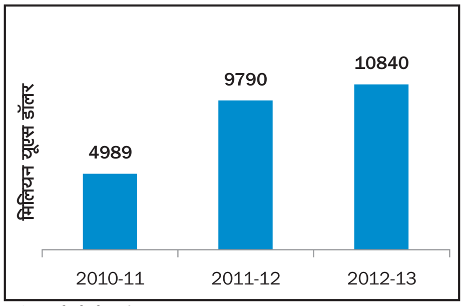

स्रोत : डीजीसीआईएस

खाद्य प्रसंस्करण मांग संवाहक

बदलती जनसांख्यिकी तथा प्रयोज्य आय में वृद्धि के चलते प्रसंस्कृत खाद्य की मांग हाल के वर्षों में बढ़ी है। खाद्य क्षेत्र में संगठित रिटेल और निजी लेबल की वृद्धि भी नये प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र घोषित किया है जिससे यह क्षेत्र रिआयती उधार के लिए पात्र हो गया है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए तीन-चार जिलों के क्लस्टर के लिए एक बड़ा फूड पार्क स्थापित करने की योजना भी बनायी है। इस अभियान से इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, लॉजिस्टिक्स तथा केंद्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना को बल मिलेगा। कृषि में मूल्य योजन को बढ़ावा देने की सरकार की नीति भी इस क्षेत्र की वृद्धि में सहायक होगी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों तथा नीति-निर्माताओं की उच्चतर सहभागिता की भी आवश्यकता है। जल्दी खराब हो जाने वाले माल के भंडारण और भरपूर उत्पादन के दौरान नुकसान को कम करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास आवश्यक है।

संदर्भ :

➢ खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेशित पूंजी

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11(पी)	एएजीआर
निवेशित पूंजी (₹ करोड़)	1,12,484	1,38,996	1,57,062	1,93,850	2,49,337	-
वृद्धि दर	22.21	23.57	13	23.42	28.62	22.17

*अचल पूंजी तथा भौतिक कार्यशील पूंजी का योग, पी - अंतिम परिणाम

स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, एमओएसपीआई

भारत के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की निर्यात संभाव्यता

भारत के पास इंजीनियरिंग कौशल, देशी बाजार, सुस्थापित कच्चा माल आधार और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के बावजूद विनिर्माणों का निर्यात अपेक्षा अनुरूप नहीं है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में 13.5 प्रतिशत हिस्सा है। वैश्विक विनिर्माण में भी भारत का हिस्सा सिर्फ 1.8 प्रतिशत है। यह अन्य एशियाई देशों जो आर्थिक विकास के उसी चरण में थे, के अनुभव के बिल्कुल विपरीत है। चीन में विनिर्माण क्षेत्र का राष्ट्रीय जीडीपी में 34 प्रतिशत और विश्व विनिर्माण (1991 के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर) में 13.7 प्रतिशत हिस्सा है। इसके चलते भारत भारी व्यापार घाटा भी उठाता है जो भारत के चालू खाता घाटे पर एक भारी दबाव डालता है।

2002 से 2012 की दस वर्षीय अवधि के दौरान भारत के विनिर्माण निर्यात का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि निर्यात के लगभग 50 प्रतिशत में कृषि एवं सम्बध्द उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद तथा रत्न एवं आभूषण उत्पाद शामिल रहे हैं। इनमें से अधिकांश उत्पाद उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुख नहीं हैं। इसी अवधि के दौरान, भारत द्वारा विनिर्मित माल का आयात निर्यात की तुलना में तीव्र गति से बढ़ा है जिससे व्यापार घाटा 2012 में 199.4 बिलियन यूएस डॉलर (44.3 प्रतिशत के सीएजीआर की दर से) तक बढ़ गया **(तालिका)**।

विनिर्माण क्षेत्र में संचयी व्यापार घाटा (30.9 बिलियन यूएस डॉलर) देश के कुल चालू खाता घाटे के एक-तिहाई के पास रहा। पूंजीगत माल, रसायन, उर्वरक, धातु तथा उत्पाद, कागज उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, रबड़, सिरॉमिक उत्पाद तथा तकनीकी/चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में व्यापार घाटा 74.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो भारत के चालू खाता घाटे के 84 प्रतिशत से अधिक रहा।

उद्योग-वार विश्लेषण से पता चलता है कि धातु तथा धातु उत्पाद, जूते तथा चमड़े के उत्पाद, प्लास्टिक, रबड़ तथा उनकी वस्तुएं जैसे कुछ क्षेत्र जो 2002 में सकारात्मक व्यापार संतुलन में थे 2012 में नकारात्मक व्यापार संतुलन में चले गए। पूंजीगत माल उत्पादों ने 2002 की तुलना में 2012 में व्यापार घाटे में महत्वपूर्ण वृध्दि (24.4 प्रतिशत सीएजीआर) प्रदर्शित की है। रसायन तथा उत्पाद, उर्वरक तथा ऑप्टिकल उत्पाद क्षेत्र ने भी विश्लेषित अवधि के दौरान व्यापार घाटे में इसी प्रकार की वृध्दि प्रदर्शित की है।

परिवहन उपकरण क्षेत्र ने सुधार प्रदर्शित किया क्योंकि इसका व्यापार घाटा उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिए ग्रीनफील्ड एफडीआई अंतर्वाह, प्रौद्योगिकी समामेलन, गुणवत्ता अनुपालन आदि के चलते विगत वर्षों में सकारात्मक हो गया।

घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की उपेक्षा से निर्यातों में मंदी आयी तथा उच्च लागत विनिर्मित उत्पादों (पूंजीगत माल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रसायन) के आयात से व्यापार घाटा बढ़ता चला। निर्यात क्षमताओं को मजबूत करके ही इस बढ़ते व्यापार घाटे पर अंकुश लगाया जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शुरू से ही भारत को एक प्रमुख वैश्विक सोर्सिंग एवं विनिर्माण केन्द्र नहीं माना है। एक प्रमुख सोर्सिंग हब बनने या चीन के विकल्प के रूप में उभरने के लिए भारत को कौशल-गहन उद्योगों में अपनी बढ़त का फायदा उठाना चाहिए और एकल-देश सोर्सिंग में अन्तर्निहित जोखिमों से बचना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र के सुदृढ़ होने से भारतीय तथा बहुराष्ट्रीय दोनों कंपनिया इस क्षेत्र में निवेश करेंगी तथा उन्हें उस अर्थव्यवस्था में अधिक जोरदार ढंग से भाग लेने का अवसर मिलेगा जिसमें विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभाव्यता है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन के लिए एक उपयुक्त परिवेश निर्मित करने पर विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में न केवल निर्यात को बढ़ावा देने की संभाव्यता है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने की भी संभाव्यता है। इससे सरकार को भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 2022 तक 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

तालिका : चुनिंदा विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापार घाटा

एचएस कोड के साथ उत्पाद विवरण	भारत का निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)		सीएजीआर (%)	भारत का आयात (बिलियन यूएस डॉलर)		सीएजीआर (%)	व्यापार संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	
	2002	2012	2002-12	2002	2012	2002-12	2002	2012
पूंजीगत माल (एचएस कोड 84, 85)	3.0	21.7	24.6	9.2	65.9	21.8	-6.2	-44.2
परिवहन उपकरण (एचएस कोड 86-89)	1.2	18.2	35.3	1.5	13.6	24.3	-0.3	4.7
रसायन एवं उत्पाद (एचएस कोड 28, 29, 32, 33, 34, 36, तथा 38)	3.73	21.2	21.4	4.3	27.0	20.2	-0.5	-5.7
उर्वरक (एचएस कोड 31)	0	0.1	-	0.4	7.9	35.4	-0.4	-7.8
औषधि उत्पाद (एचएस कोड 30)	1.2	9.6	25.3	0.2	1.8	23.2	1.0	7.8
टेक्सटाइल, वेश-भूषा एवं उत्पाद (एचएस कोड 50-63)	11.3	32.6	12.5	1.6	5.2	12.4	9.8	27.5
धातु एवं उत्पाद (एचएस कोड 72, 73, 74, 76, व 79 से 83)	3.7	21.7	21.4	2.4	26.2	27.1	1.4	-4.4
कागज व पेपर बोर्ड; पल्प, पेपर तथा बोर्ड की वस्तुएं (एचएस कोड 48)	0.2	0.9	15.7	0.4	2.3	18.6	-0.2	-1.3
मुद्रित पुस्तकें, समाचार-पत्र, चित्र आदि (एचएस कोड 49)	0.07	0.3	19.2	0.2	0.7	12.3	-0.1	-0.3
जूते, चमड़ा, पशु-मूल के उत्पाद (एचएस कोड 42, 43, 64)	0.8	4.0	18.6	0.0	0.6	33.1	0.8	3.4
प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं (एचएस कोड 39)	0.9	4.9	20.0	0.9	9.3	26.5	0.1	-4.3
रबड़ और उसकी वस्तुएं (एचएस कोड 40)	0.4	2.7	21.1	0.3	3.9	27.5	0.1	-1.1
सिरॉमिक उत्पाद (एचएस कोड 69)	0.1	0.4	17.9	0.1	0.7	26.7	0.0	-0.3
ऑप्टिकल, फोटो, तकनीकी, चिकित्सा आदि उपकरण (एचएस कोड 90)	0.3	2.1	22.0	1.3	6.9	18.3	-0.9	-4.8
उपर्युक्त का योग	***27.4***	***140.8***	***19.9***	***22.8***	***171.7***	***22.4***	***4.6***	***-30.9***
सभी पण्य	***50.1***	***289.5***	***21.5***	***57.5***	***489.0***	***23.9***	***-7.4***	***-199.4***

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

12 सीएलएमवी क्षेत्र में निवेश अवसर

सीएलएमवी देश, जिनमें कम्बोडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओ पीडीआर), म्यांमार तथा वियतनाम शामिल हैं, आसियान क्षेत्र के अभिन्न भाग हैं। ये देश आसियान क्षेत्र के 32 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं और आसियान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनका लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा है। ये देश केन्द्रीय आयोजना से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, अन्तर्मुखी रणनीतियों से बहिर्मुखी आर्थिक नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं। सीएलएमवी अर्थव्यवस्थाएं, जिन्हें क्षेत्र में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं माना जाता है, मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनमें भावी विकास की विपुल संभाव्यता है। हाल के वर्षों में इनमें आर्थिक स्थिरता भी आई है। यद्यपि ये अर्थव्यवस्थाएं विपुल प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते श्रम से सम्पन्न हैं किन्तु अल्प विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर तथा लॉजिस्टिक समस्याओं से ग्रसित हैं।

एफडीआई आकृष्ट करने के उद्देश्य से, कम्बोडिया सरकार ने देश के कानूनी ढांचे व अपनी संस्थाओं को मजबूत किया है और संबंधित विनियमों को इस ढंग से उदार बनाया है कि वे कम्बोडिया में निजी क्षेत्र के निवेश और कारोबारी कार्यकलापों के लिए अनुकूल हों। कम्बोडिया की खुली अर्थव्यवस्था, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और सस्ती श्रमशक्ति निवेशकों के लिए कई अवसर प्रदान करती है। देश में निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण, इंफ्रास्ट्रक्चर-रेल, सड़क, पुल, बिजली पारेषण, परिवहन, संचार, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्र; उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग शामिल हैं।

एफडीआई लाओ पीडीआर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अधिकांश निवेश वर्तमान में हाइड्रोपॉवर तथा खनन क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं तथा कुल एफडीआई का लगभग तीन-चौथाई है। देश में हाइड्रोपॉवर उत्पादन की अच्छी संभाव्यता है। इसी तरह देश में विपुल खनिज संपदा है, जिसमें से सिर्फ 30 प्रतिशत संपदा का उपयोग किया गया है। इस क्षेत्र में भी निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। अधिकाधिक निवेश कृषि व्यवसाय, पर्यटन तथा अन्य सेवा उद्योगों में हो रहे हैं। लाओ, चीन, थाईलैंड तथा वियतनाम के बीच स्थित है तथा एक भूमि-अवरूध्द देश है। सरकार ने व्यापार तथा निवेश अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन सम्पर्कों में सुधार पर काफी जोर दिया है। इसके अलावा, सरकार ने 2020 तक 90 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। लाओ पीडीआर में कौशल की कमी व्यवसाय तथा निवेशकों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार कौशल में सुधार निवेश के एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में रखा गया है।

म्यांमार में हुए हालिया सुधार तथा इसकी रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता विभिन्न प्रकार के आर्थिक अवसर खोलते हैं। ऐसी आशा है कि 2030 तक सात क्षेत्र, नामत : विनिर्माण, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय सेवा तथा दूर-संचार 200 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक आर्थिक उत्पादन उत्पन्न कर सकते हैं। दूर-संचार क्षेत्र (मोबाइल, टेलीफोन सहित) निवेश का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि इस देश में 1.5 प्रतिशत की न्यून मोबाइल व्यापन दर और 0.2 प्रतिशत की इंटरनेट व्यापन दर है। म्यांमार का वित्तीय क्षेत्र, जो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से अलगाव के कारण अब भी अपेक्षाकृत अल्प विकसित है, भी सहयोग के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन म्यांमार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत लगभग 103.7 केडब्ल्यूएच है। सस्ते श्रम की प्रचुरता वस्त्र क्षेत्र सहित श्रम गहन तथा निर्यातोन्मुख विनिर्माण क्षेत्र में अवसर प्रदान करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें रेल, सड़क, वायु, पत्तन की कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स तथा जल आपूर्ति शामिल है। अनुमान है कि 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 49 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान दे सकता है। देश की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र में भी अपार संभाव्यता है। म्यांमार में तटीय (ऑनशोर) तथा अपतटीय (ऑफशोर) दोनों ही क्षेत्रों में तेल तथा गैस के विशाल भंडार हैं। साथ ही म्यांमार में जेड, माणिक्य (रूबी) तथा नीलम (सफायर) प्रचुर मात्रा में हैं।

वियतनाम में निवेश के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हेल्थकेयर, विनिर्माण तथा अनुषंगी उद्योग शामिल हैं।

सीएलएमवी क्षेत्र में नये आर्थिक अवसर पर सम्मेलन

नई दिल्ली में 21-22 अक्तूबर, 2013 के दौरान सीएलएमवी बिजनेस कॉनक्लेव का आयोजन किया गया। इस सभा में अल्प विकसित देशों के आसियान समूह में विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के लिए निवेश संभाव्यता पर प्रकाश डाला गया। इसमें सीएलएमवी देशों से 50 से अधिक सदस्यों के प्रतिनिधि मंडलों और भारत से 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपस में मजबूत कारोबारी संबंध विकास करने पर विशेष सत्र के साथ सभा का शुभारंभ हुआ। सत्र के दौरान यह सूचित किया गया कि भारत तथा सीएलएमवी देशों के बीच मजबूत संबंधों से न केवल द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक-दूसरे के समीप लाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया कि भारत-सीएलएमवी संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं अच्छी प्रगति कर रही हैं अतः अब ऐसा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित करने पर फोकस होना चाहिए जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभावी उपयोग करते हुए दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों तथा माल के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाए।

बाजार सलाहकारी सेवाएं

अक्तूबर - दिसम्बर 2013

बैंक अपनी विपणन सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता सृजित करने तथा उसे बढ़ावा देने में संवर्धनात्मक भूमिका अदा करता है । बैंक भारतीय फर्मों को सफलता शुल्क आधार पर उनके उत्पादों तथा सेवाओं के लिए विदेशी क्रेताओं तथा वितरकों की पहचान कर उनके भूमंडलीकरण प्रयासों में सहायता प्रदान करता है ।

एक्ज़िम बैंक के शोध एवं आयोजना समूह ने भारतीय बागवानी पर एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया है जिसमें आम तथा आम के प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए निर्यात संभाव्यता का दोहन करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है ।

विभिन्न प्रकार के उष्णकटिबंधी (ट्रॉपिकल)फलों के गूदा (पल्प), पियरी तथा सब्जी पाउडर के मुंबई के एक विनिर्माता तथा निर्यातक ने अपनी विनिर्माण इकाई के विस्तार और नियमित कार्यशील पूंजी के लिए ऋण हेतु एक्ज़िम बैंक से संपर्क किया ।

बैंक ने यूके आधारित एक आयातक से संपर्क किया और इस निर्यातक का उससे परिचय कराया । एक्ज़िम बैंक के लंदन कार्यालय की सहायता और गहन फालो-अप से निर्यातक को टिन पैकिंग में अपने आम पल्प के लिए 12 महीने की अवधि के दौरान दस से अधिक ऑर्डर मिले। एक्ज़िम बैंक की सहायता से न केवल उत्पाद सफलतापूर्वक पेश किया गया, बल्कि उपभोक्ताओं से अच्छा प्रतिसाद मिला और निर्यातक का वैश्विक बाजार में ग्राहक आधार बढ़ा । बाद में, अतिरिक्त ऑर्डर भी मिले और बैंक सुझावों के आधार पर निर्यातक द्वारा मूल्य योजन किये जा रहे हैं ।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
मुंबई
फोन : (022) 22172829
ई-मेल : deepali@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस केन्द्र कार्यकलाप

अक्तूबर - दिसम्बर 2013

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) के सहयोग से 24-25 सितम्बर 2013 को पूर्वोत्तर राज्यों पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन चाय, मसाले, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, परिधान आदि में पूर्वोत्तर राज्यों की संभाव्यता का विश्लेषण करने और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ।

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कोचिन और कोलकाता में क्रमशः 4 तथा 8 अक्तूबर 2013 को सेवा क्षेत्र पर परस्पर चर्चा सत्रों का आयोजन किया । इस बैठक का उद्देश्य अंशधारकों से प्रत्युत्तर तथा फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से चुंनिंदा सेवा प्रदाताओं और संस्थाओं संघों के साथ चर्चा करना था । यह सुझाव भारत के सेवा क्षेत्र तथा निर्यात के लिए भारत सरकार की रणनीति के लिए मुख्य निविष्टियों का काम करेंगें । बैठकों की अध्यक्षता डॉ. एच ए सी प्रसाद, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार तथा अवर सचिव, वित्त मंत्रालय द्वारा की गई ।

एक्ज़िमिअस केन्द्र और एफआईईओ ने बेंगलोर में 17 अक्तूबर, 2013 को 'वियतनाम में व्यापार तथा निवेश अवसर' पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वियतनाम में व्यापार और निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों तथा एक्ज़िम बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना था ।

एक्ज़िमिअस केन्द्र और विश्वेसरैया व्यापार संवर्धन परिषद (वीटीपीसी) ने धारवाड़, हुबली तथा बेंगलोर में जून, जुलाई तथा अगस्त महीनों के दौरान निर्यात प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह कार्यक्रम निर्यातकों तथा उदीयमान निर्यातकों के लाभ के लिए आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य निर्यात कारोबार के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना भी था ।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री टी. वी. राव
सलाहकार - एक्ज़िमिअस केन्द्र
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
बेंगलोर
फोन : (080) 25589106
ई-मेल : eximius@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

रिइमेजिंग इंडिया : अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एशियाज़ नेक्स्ट सुपरपॉवर

यह पुस्तक 82 अग्रणी भारतीय तथा वैश्विक चिंतकों, जिनमें उद्योगपति, शिक्षाविद् तथा विश्व के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शामिल हैं, द्वारा भारत की चुनौतियों तथा अवसरों पर लिखे गये 60 से अधिक लेखों का संकलन है । पुस्तक एशिया की अगली महाशक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर भारत की चिंताओं के बारे में विचार प्रस्तुत करती है । पुस्तक एशिया की अगली महाशक्ति भारत पर नया चिंतन प्रस्तुत करती है जो विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी ऐतिहासिक प्रमुखता का दावा कर रहा है ।

हाल ही में कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक मंदी से उभरने के लिए संघर्ष किया। भारत और चीन विश्व के दो अपरिहार्य उभरते बाजारों के रूप में स्थापित हो रहे हैं। 1.2 बिलियन जनता (जिसमें से आधी 25 वर्ष से कम आयु की है) के साथ भारत 2025 से पूर्व विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन से आगे निकल जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था ने भी गत वर्षों में चीन की तरह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को प्रदर्शित किया है ।

विश्वास से लबरेज भारत की अग्रणी कंपनियां विदेशों में भारी-भरकम अधिग्रहणों से सुर्खियां बटोर रही हैं । भारतीय कंपनियां अपनी कार्यकुशलता तथा नवोन्मेषण क्षमता प्रदर्शित करते हुए फार्मास्युटिकल, पेट्रोरसायन तथा इस्पात जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कदम रख रही हैं जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बदल रहा है ।

पुस्तक में भारत की राजनीतिक प्रणाली की शक्तियों तथा कमजोरियों, भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाओं, भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता और भारत की विदेश नीति पर लेख शामिल हैं । पुस्तक इन संभावनाओं का पता लगाती है कि भारत नई प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर सकता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुधार सकता है, हेल्थकेयर तक पहुँच कैसे बढ़ा सकता है, अपनी शिक्षा प्रणाली को नया रूप कैसे दे सकता है, अपनी ऊर्जा नीति पर कैसे पुनः चिंतन कर सकता है और अपने पर्यावरण के विनाश को कैसे रोक सकता है । पुस्तक में लोकप्रिय विषयों जैसे बॉलीवुड, क्रिकेट, भारतीय व्यंजन, शतरंज, शास्त्रीय नृत्य, तथा ओलम्पिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन पर भी लेख हैं ।

घाना

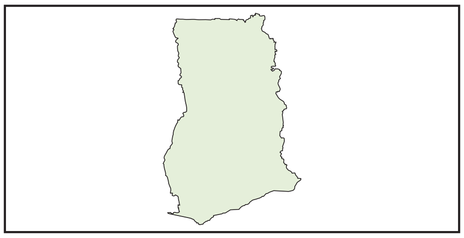

अक्तूबर 2013 में जारी अंकटाड की वैश्विक निवेश प्रवृत्ति मॉनिटर (जीआईटीएम) रिपोर्ट के अनुसार, घाना में एफडीआई प्रवाह 2012 की दूसरी छमाही के दौरान 1.6 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 2013 की पहली छमाही के अंत में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा। उसी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मोटर निर्माता, महिन्द्रा स्थानीय घानाई फर्म की भागीदारी में एक वाहन असेम्बली प्लांट स्थापित करने के प्रयास में है जिससे तेल तथा खनन से भिन्न क्षेत्रों में निवेशों के विशाखन को मदद मिलेगी। घाना ने देश के संरचनात्मक घाटे पर ध्यान देने के लिए एक विशिष्ट निधि स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की है। विश्व बैंक ने हाल ही में घाना को अफ्रीका के ऐसे चौथे देश के रुप में रखा है जिस पर अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य की तुलना में उच्चतम लोक ऋण है। अगस्त 2013 में विश्व बैंक ने घाना को 10 बिलियन यूएस डॉलर राशि की सहायता प्रदान की जिसमें से अधिकांश राशि-विश्व के निर्धनतम देशों के लिए बैंक की सुविधा-अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) से प्राप्त हुई है। कुल निधीयन में से लगभग 8 बिलियन यूएस डॉलर की राशि-सरकार को अनुदान तथा ब्याज मुक्त ऋण के रुप में थी।

तंजानिया

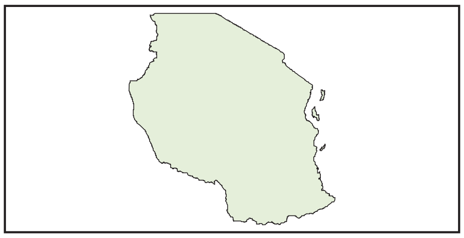

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, तंजानिया द्वारा 2014 में 7 प्रतिशत से अधिक की वृध्दि दर हासिल करने का अनुमान है। तंजानिया के राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो के अनुसार, 2013 की दूसरी तिमाही में, अर्थव्यवस्था गत वर्ष में 6.4 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत बढ़ी। नवम्बर में, यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) ने तंजानिया में चार कृषि परियोजनाओं में कुल 20 मिलियन जीबीपी की राशि निवेश करने की योजना की घोषणा की। यह निवेश योजना विदेशी सहायता में कटौती करने और स्थानीय उद्यमों में निवेश कर और कारोबार करने वाली यूके की कंपनियों की सेवाएं बढ़ाकर तंजानिया में आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने की यूके की योजना का भाग है। तंजानिया तथा चीन ने भी बिजली, आवासीय तथा व्यावसायिक स्थावर-संपदा निर्माण और अनुसंधान के क्षेत्रों में निवेश के लिए कुल 1.7 बिलियन यूएस डॉलर की सात संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं।

उज़बेकिस्तान

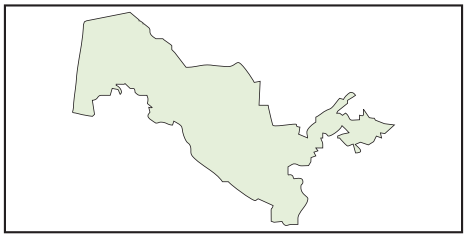

उज़बेकिस्तान कपास के विश्व में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और तेल, गैस तथा स्वर्ण सहित प्राकृतिक संसाधनों से भी संपन्न है। एशियाई विकास बैंक उज़बेकिस्तान में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए समरकंद, उज़बेकिस्तान में एक 100 मेगावॉट सौर बिजली संयंत्र के लिए कुल 110 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। हाल ही में, उज़बेकिस्तान की सरकारी रेलवे कंपनी उज़बेकिस्तान टेमिर युल्लारी (उज़बेकिस्तान रेल) ने देश के दक्षिण में 466 किमी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के लिए उपकरणों की खरीद हेतु निविदाओं की घोषणा की है। 2019 तक उज़बेकिस्तान रेल ने कुल 715 किमी. लम्बी रेलवे लाइनों के साथ तीन रेल खंडों के विद्युतीकरण के लिए 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की राशि खर्च करने की योजना बनायी है। इससे उज़बेक दक्षिण, जो कई विशाल निवेश परियोजनाओं का केन्द्र है, को तथा से यात्री तथा माल-भाड़ा यातायात में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। रेलवे विद्युतीकरण से पड़ोसी देश अफगानिस्तान को माल-भाड़ा परिवहन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उज़बेकिस्तान की राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी उज़बेकनर्जो एक नये गैस ईंधन आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शुरू करेगी जिससे नवोई खनन तथा धात्विक संयंत्र को बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी।

चिले

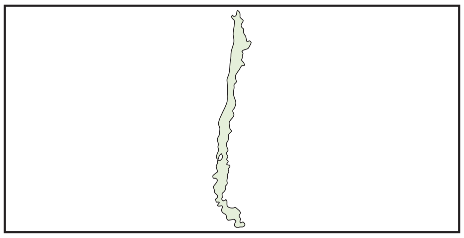

चिले का केन्द्रीय बैंक 2013 में आर्थिक वृध्दि दर घटकर 4.2 प्रतिशत हो जाने की प्रत्याशा और प्रत्याशित से कमजोर देशी माँग के बीच 2014 के दौरान वृध्दि तथा मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान में कटौती की है। केन्द्रीय बैंक ने पिछले दो महीने में आधार ब्याज दर में दो बार कटौती की है क्योंकि देशी माँग कमजोर हुई और मुद्रास्फीति की दर 2-4 प्रतिशत लक्ष्य रेंज से नीचे आ गई। चिले विश्व में शीर्ष तांबा उत्पादक है और अपने व्यापारिक भागीदार से धातु की भारी माँग से इसे काफी फायदा हुआ है। चिले पर अपने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में, ओईसीडी ने देश में कर प्रणाली में सुधार के बारे में सूचित किया है, विश्व बैंक ने 'डुइंग बिजनेस' रिपोर्ट के अपने अद्यतन संस्करण में चिले को 189 देशों की सूची में 34 वें स्थान पर रखते हुए लैटिन अमेरिका में कारोबार करने के लिए इसे सर्वोत्तम देश का दर्जा दिया है।

फिलीपीन्स

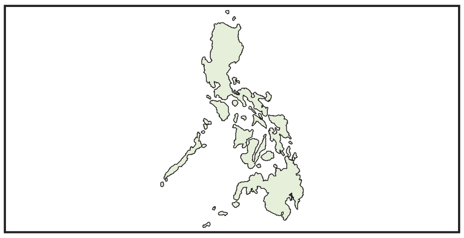

बजट एवं प्रबंध विभाग (डीएमबी) के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य पूंजी परिव्यय के लिए सरकारी व्यय 2013 के पहले 9 महीनों में 33.9 प्रतिशत बढ़ा। अक्तूबर 2013 में, फिलीपीन्स ने मूडीज से क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड प्राप्त होने के बाद निवेश ग्रेड दर्जे में अपना रुपान्तरण पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) ने अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2013 में फिलीपीन्स को विश्व में शीर्ष 20 निवेश गंतव्य स्थानों में रखा है।

यूरो (ईयूआर)

यूरो का प्रबंध और नियंत्रण यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक के रूप में ईसीबी मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, ईसीबी का मुख्य कार्य यूरो की क्रय शक्ति को बनाए रखना और इस प्रकार यूरो क्षेत्र में मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

वर्तमान परिस्थितियों में, यूरो में वृध्दि इस तथ्य को देखते हुए उपयुक्त है कि यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पुनरूत्थान के संकेत मिले हैं। बेरोजगारी की ऊंची दरों पर तुरंत अंकुश लगाना या राजकोषीय संतुलन में जोरदार चक्रीय सुधार लाना असंभव है। मुद्रास्फीति कोई मुद्दा नहीं रह गया है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्तमान में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 0.7 प्रतिशत के न्यून स्तर पर है, वस्तुतः अवस्फीति की आशंका बढ़ रही है। ऐसे कमजोर आधार के साथ सुधार मजबूत यूरो को आसानी से पचा नहीं सकता है। ब्याज दर में कमी ही स्पष्टतः एक संभाव्य साधन है। उदाहरण के लिए, नवम्बर में, ब्याज दरों में कटौती करने के निर्णय के फलस्वरूप यूरो-यूएस डॉलर की विनिमय दर में 1.35 से 1.33 की गिरावट आयी। वस्तुतः यूरो मध्यावधि ब्याज दरों की प्रत्याशा में सामान्यतः वृध्दिशील सहसंबंध दर्शाता है। राष्ट्रपति ड्रैघी ने यह स्पष्ट किया कि ब्याज दरों में और कटौती की संभावना है। उन्होंने बाजार को याद दिलाया कि पुनर्वित्तपोषण दर अभी तक शून्य सीमा पर नहीं है और ईसीबी नकारात्मक ब्याज दर के लिए तकनीकी रूप से तैयार है।

नवम्बर में ईसीबी द्वारा ब्याज दरों में कटौती का निर्णय प्रत्याशित से कम मुद्रास्फीति द्वारा प्रभावित हो सकता है। यूरो क्षेत्र में संभावित नरमी और यूएस में संभावित मौद्रिक नरमी से निकलने के चलते मौद्रिक नीति यूरो क्षेत्र तथा यूएस में असामान्य रूप से विपरीत दिशाओं मे जा रही है। यह एक ऐसा समूहन है जो यूरो-यूएस डॉलर को नीचे ले जाएगा और बाजार को उम्मीद है कि यूरो वर्ष के अंत तक लगभग 1.30 और 2014 के अंत तक 1.24 के स्तर पर रहेगा। यूरो 31 दिसम्बर, 2013 को 1 यूरो = 1.3776 यूएस डॉलर पर उध्दृत हो रहा था।

चीनी युआन (सीएनवाई)

चीनी युआन फेडरल खुला बाजार समिति (एफओएमसी) की अक्तूबर बैठक के बाद से उत्कृष्ट एशियाई मुद्रा रही है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) द्वारा विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति ने अंतर-बैंक लिक्विडिटी को अपेक्षाकृत कठोर रखा है। आर्थिक आंकड़े देशी अर्थव्यवस्था में स्थिरता दर्शाते हैं। इसके अलावा, पीबीओसी ने यूएस डॉलर की नई शक्ति के बावजूद तटीय चीनी युआन नियत दर को न्यून रखना जारी रखा है। इससे दायरे के व्यापक होने तथा विदेशी मुद्रा में और सुधार की संभावना बढ़ गयी है। बाजार को प्रत्याशा है कि नीति-निर्माता युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण और पूंजी खाता उदारीकरण उपायों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। बाजार विदेशी मुद्रा उदारीकरण तथा पूंजी परिवर्तनीयता पर अधिक विस्तृत उपायों की प्रत्याशा करता है।

पीबीओसी के हालिया दैनिक विदेशी मुद्रा परिचालन - यूएस डॉलर - युआन नियत में हस्तक्षेप तथा उतार-चढ़ाव - यह सुझाते हैं कि विदेशी मुद्रा का उदारीकरण निकट भविष्य में यूएस डॉलर - युआन के दैनिक ट्रेडिंग दायरे में हो सकता है। पूर्ण बैठक के बाद नियमों की घोषणा हो जाने पर नया शंघाई मुक्त व्यापार क्षेत्र शुरू हो जाना चाहिए। क्षेत्र कालांतर में अपतटीय युआन की लिक्विडिटी बढ़ाते हुए युआन की परिवर्तनीयता के लिए परीक्षण आधार होगा। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार तीसरी तिमाही में बढ़कर 166 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो 2011 की पहली तिमाही के बाद सबसे बड़ी तिमाही वृध्दि है। विदेशी मुद्रा अंतर्वाह दूसरी तिमाही के उत्तरार्ध में मामूली निवल बहिर्वाह दर्ज करने के बाद तेजी से बढ़ा है। मजबूत अंतर्वाह दबाव युआन के पक्ष में हैं किन्तु बाजार संचालित विदेशी मुद्रा सुधार शुरू करने का प्रयास करते समय यह प्राधिकारियों के लिए चुनौती बन सकता है। 31 दिसम्बर, 2013 को युआन 1 यूएस डॉलर = 6.0540 युआन पर उध्दृत हो रहा था।

मेक्सिकन पेसो (एमएक्सएन)

मेक्सिकन पेसो अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था के अधीन प्रबन्धित है। विनिमय आयोग में वित्त सचिवालय तथा केन्द्रीय बैंक के सदस्य शामिल हैं। मेक्सिको ने यूएस डॉलर भंडार संचित करने के लिए एक विकल्पी व्यवस्था और अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था के सिध्दांत को छेड़े बिना मुद्रा की अस्थिरता को कम करने के लिए यूएस डॉलर बिक्री योजना लागू की है।

मंद देशी वृध्दि, भारी राजकोषीय घाटे और बढ़ते अमेरिकी प्रतिलाभ के अनुरूप सभी उभरते बाजारों में मजबूत यूएस डॉलर सहित कई वजहों से मेक्सिकन पेसो कमजोर हुआ है। तथापि मेक्सिकन पेसो में तीन वजहों से सुधार की गुंजाइश है - पहला, यूएस डॉलर प्रतिलाभ अधिक नहीं बढ़ेगा। दूसरा, मेक्सिको की वृध्दि में उछाल आएगा (अर्थशास्त्री 2014 में 4.1 प्रतिशत की उम्मीद करते हैं) और तीसरा अमेरिकी सुधार अंततः मेक्सिकन परिसंपत्तियों के लिए सकारात्मक सिध्द होंगे। वर्ष के अंत तक पारित किये जाने वाले ऊर्जा सुधारों से बाजार में अप्रत्याशित उछाल आ सकता है।

सरकार ने संकेत दिया है कि वह विदेशी तेल कंपनियों के लाभ-हिस्सेदारी संविदाओं का समर्थन करेगी किंतु मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं या रियायतों पर भी विचार करेगी। इससे विदेशी निवेश में तेजी आ सकती है और मेक्सिकन पेसो में वर्तमान स्तरों से सुधार की अधिक गुंजाइश होगी। 31 दिसम्बर, 2013 को विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 13.0995 मेक्सिकन पेसो थी।

भारत के व्यापार घाटे में 13.4% की कमी

2013-14 की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान भारत का विदेश व्यापार (निर्यात + आयात) गत वर्ष में मंदी के बाद सुधार की ओर अग्रसर है। भारत का निर्यात गत वर्ष के 144.7 बिलियन यूएस डॉलर (6.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए) की तुलना में 5.2 प्रतिशत बढ़कर 152.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। जबकि आयात गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 236.5 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 231.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा जिसमें 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निर्यात में वृध्दि और आयात में गिरावट मुख्यतः वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में थी **(चार्ट 1)**। तद्नुसार, भारत का व्यापार घाटा गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान 91.8 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 13.4 प्रतिशत घटकर 79.5 बिलियन यूएस डॉलर रह गया।

मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों (जो 17.6 प्रतिशत बढ़ा), टेक्सटाइल (13.3 प्रतिशत) तथा रसायन (5.8 प्रतिशत) के निर्यात में वृध्दि की बदौलत राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान निर्यात में 5.2 प्रतिशत की वृध्दि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान भारत के समग्र निर्यात ने जबर्दस्त सुधार प्रदर्शित किया है किन्तु भारत के इंजीनियरिंग माल के निर्यात में वृध्दि, जिसका भारत के निर्यात समूह में दूसरा सबसे बड़ा योगदान है, इस अवधि के दौरान 0.9 प्रतिशत की मंद गति पर थी। इंजीनियरिंग माल में मशीनरी एवं उपकरणों (3.8 प्रतिशत) तथा परिवहन उपकरणों (3.3 प्रतिशत) में वृध्दि धातु विनिर्माण के निर्यात में गिरावट (9.6 प्रतिशत) द्वारा समंजित हो गई।

जहां तक आयात का संबंध है, भारत द्वारा अपरिष्कृत पेट्रोलियम के आयात में वृध्दि, जिसका भारत के कुल आयात में 35.8 प्रतिशत हिस्सा रहा, गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान 5.8 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 की पहली छमाही के दौरान 3.7 प्रतिशत रही। मशीनरी आयात, जिसका भारत के कुल आयात में 9.1 प्रतिशत हिस्सा रहा, में 2013-14 की पहली छमाही में 13.2 प्रतिशत की गिरावट आयी।

भारत से निर्यात के लिए यूरोपीय देशों से माँग में 2013-14 में सुधार हुआ। यूरोपीय देशों को भारत का निर्यात गत वर्ष की अनुरूपी अवधि में दर्ज की गई 10.9 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2013-14 की पहली छमाही के दौरान 5.4 प्रतिशत बढ़ा।

जहां तक आयात का संबंध है, भारत के मशीनरी आयात के लिए सबसे बड़े स्त्रोत चीन से भारत के आयात में 2013-14 की पहली छमाही के दौरान 4.1 प्रतिशत की गिरावट आयी। यूएई तथा यूएसए से भी आयात में 2013-14 की पहली छमाही के दौरान क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7.8 प्रतिशत की गिरावट आयी।

भारत के विदेशी निर्यात में सुधार के चलते भारत सरकार ने एशिया (आसियान सहित), अफ्रीका तथा अमेरिका पर विशेष ध्यान के साथ 2013-14 में 325 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है।

वर्ष के दौरान, सरकार ने सोने, प्लेटिनम तथा चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने सहित अपने आयात बिल को कम करने के लिए कई कदम उठाये। विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए, बाह्य वाणिज्यिक उधार मानदंडों को उदार बनाने, दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अर्ध-सरकारी बांड जारी करने और सॉवरिन वेल्थ फंडों को कुछेक सरकारी संस्थाओं को कर-मुक्त बांडों में निवेश करने की अनुमति देने सहित कई उपायों की घोषणा की गई।

चार्ट 1 : भारत का विदेश व्यापार - मासिक विश्लेषण (बिलियन यूएस डॉलर)

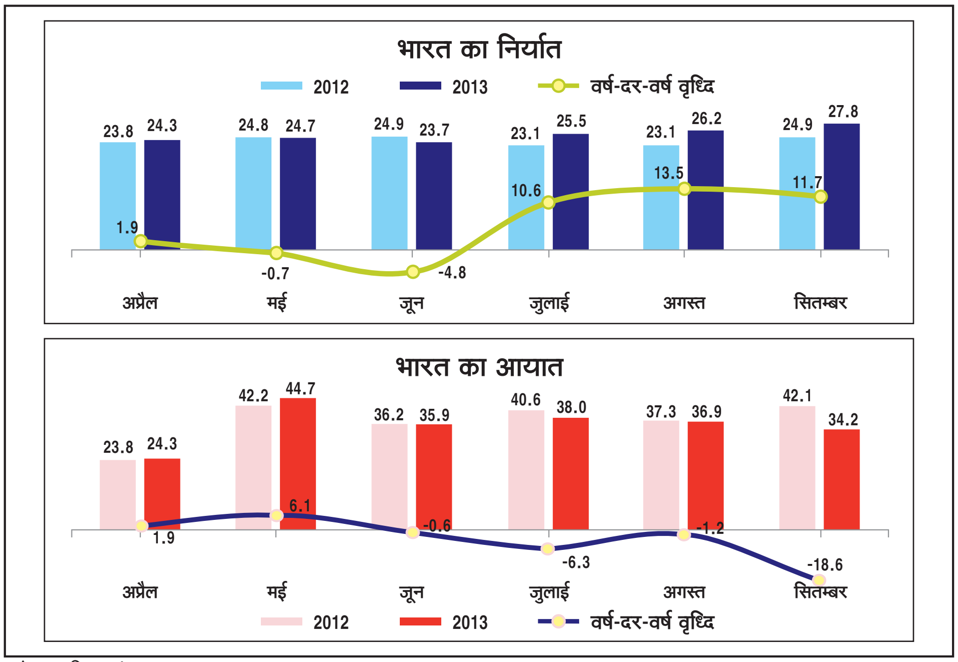

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्त्रोतों / माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रामाणिक हैं। प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रामाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है।

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है

1 करोड़ : 10 मिलियन

1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005
दूरभाष : +91-22-2217 2600
फैक्स : +91-22-2218 2572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ - फीडबैक (प्रतिपुष्टि) फार्म

कृपया इसे और बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें ।

1. आप किससे संबंधित हैं *(जो लागू हो उस पर टिक करें)*
   - ☐ सरकारी संस्था
   - ☐ गैर-सरकारी संस्था
   - ☐ कार्पोरेट
   - ☐ निर्यातक
   - ☐ शैक्षणिक संस्था
   - ☐ व्यक्तिगत
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें......* ________

2. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आपके विचार
   - ☐ समझने में आसान एवं उपयोगी
   - ☐ थोड़ा सहायक
   - ☐ व्यापक
   - ☐ बिल्कुल उपयोगी नहीं

3. आप किस क्षेत्र में रूचि रखते हैं? *(कृपया टिक करें)*
   - ☐ क्षेत्रीय/औद्योगिक परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें* ________
   - ☐ देश/क्षेत्रीय परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें* ________
   - ☐ व्यवसाय अवसर एवं संविदा
   - ☐ एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएँ
   - ☐ तिमाही समाचार
   - ☐ देशों का अवलोकन
   - ☐ मुद्रा की प्रवृत्तियाँ
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें......* ________

4. क्या आप हमारे प्रकाशन से संतुष्ट हैं?
   - ☐ बेहद संतुष्ट
   - ☐ संतुष्ट
   - ☐ सामान्य
   - ☐ असंतुष्ट

5. क्या हमारा प्रकाशन आपके लिए उपयोगी रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ इसने काफी मदद की
   - ☐ यह उपयोगी रहा
   - ☐ कह नहीं सकते
   - ☐ यह उपयोगी नहीं रहा
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें......* ________

6. आपको हमारा प्रकाशन कब से मिल रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ एक वर्ष से कम समय से
   - ☐ लगभग 1-3 वर्ष से
   - ☐ लगभग 3-5 वर्ष से
   - ☐ 5 वर्ष से अधिक समय से

7. आप यह प्रकाशन किस भाषा में चाहेंगे?
   - ☐ अंग्रेजी
   - ☐ हिन्दी

8. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
   - ☐ हाँ
   - ☐ नहीं

   यदि हाँ, तो कृपया लिखें!

____

कृपया अपने सुझाव/फीडबैक हमें फैक्स/ई-मेल/डाक से निम्नलिखित पते पर भेजें : निगमित कार्य समूह, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ परेड, मुंबई - 400 005

फैक्स : +91-22 22182572, ई-मेल : cag@eximbankindia.in

नाम : ________

संपर्क विवरण : ________